



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125102

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19251/2026

रणजीत सिंह

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता	:	रविशंकर त्रिपाठी
विपक्षी के अधिवक्ता	:	जी.ए., रोहित शरण तोमर

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रवि शंकर त्रिपाठी, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रोहित शरण तोमर की ओर से पेश अधिवक्ता श्री एम.एस. तोमर और राज्य की ओर से पेश विद्वान ए.जी.ए. श्री राकेश कुमार मिश्रा को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 400/2025, बी.एन.एस. की धारा 137(2), 87, 65(1) और धारा 3/4(2), 5(एल)/6 यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत पुलिस स्टेशन कलां, जिला शाहजहांपुर में मुकदमा लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
- आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं था, जिसमें यह कहा गया है कि सूचनाकर्ता की बेटी घर से चली गई और उसके बाद वापस नहीं लौटी। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि जब पीड़िता वापस लौटी, तो बी.एन.एस.एस. की धारा 180 और 183 के तहत उसके बयान दर्ज किए गए, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा कि अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसने खुद ही अपना घर छोड़ दिया था और आवेदक को बुलाया था। इसके बाद, वे दोनों पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहते थे और आवेदक द्वारा उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया गया है।

4. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि पीड़ित की आयु 16 वर्ष है, और आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है; इसलिए, हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और 13.01.2026 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य के लिए विद्वान एजीए ने जमानत के लिए प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सके।

6. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियाँ और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्तों की मिलीभगत को ध्यान में रखते हुए और निचली अदालतों के समक्ष भीड़भाड़ वाली जेलों और आपराधिक मामलों के भारी लंबित मामलों को ध्यान में रखते हुए साथ ही **2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** रिपोर्ट किए गए **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के जनादेश पर विचार करना के साथ-साथ **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन इला. 6765** के मामले में जमानत देने के संबंध में दिशा निर्देशों को देखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर विस्तार का हकदार है। तदनुसार, वर्तमान आवेदन प्रार्थना पत्र **स्वीकार** की जाती है।

7. उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक- **रंजीत सिंह** को निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए: -

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



i. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

ii. आवेदक किसी भी स्थगन की मांग किए बिना ईमानदारी से परीक्षण/जांच में सहयोग करेगा।

iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी भी अपराध में शामिल नहीं होगा।

iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. बंधपत्र स्वीकार करने से पहले आवेदक और जमानतदार की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण को संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

10. आवेदक के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड के साथ-साथ जमानतदारों का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

11. यह भी निर्देश दिया जाता है कि ट्रायल कोर्ट आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगा।

12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह संदर्भ: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 में जमानत देने की नीति रणनीति जो (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट किया गया, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 31.01.2023 के आदेश और रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025 में पीला पाहन @ पीला पाहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य, के मामले में दिनांक 29.05.2026 के आदेश का पालन करते हुए इस आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक, शाहजहांपुर के ज़रिए ईमेल या ई-प्रिज़न पोर्टल से 24 घंटे के अंदर आवेदक को और ई-मोड के माध्यम से विचारण न्यायालय को प्रेषित करें।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

3 जून, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।